संकल्पना पत्र

आयोजन : राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच (FANS)

अंतर्राष्ट्रीय तरंग संगोष्ठी

पाकिस्तान अनाधिकृत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

भविष्यगत दृष्टिकोण और विमर्श में परिवर्तन

31 अक्टूबर, 2020,

पाकिस्तान ने 1947 से ही अनाधिकारपूर्वक जम्मू-कश्मीर (PoJK) और गिलगित-बाल्टिस्तान पर कब्ज़ा कर रखा है। अभी विगत कुछ दिनों पहले ही वहाँ राजनैतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के द्वारा किये गए चुनाव कराने के प्रयास को असंवैधानिक करार दिया है। पाकिस्तान सरकार और उसके न्यायपालिका को इस क्षेत्र पर इस प्रकार बलपूर्वक और अनैतिक रूप से कब्ज़ा करने का कोई भी ठोस कारण और वैधानिक शक्ति नहीं है। गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अनाधिकृत क्षेत्र के राजनैतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गिलगित, हुंजा और बाल्टिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन के संदर्भ में आवाज उठाई है। इसी कारण वर्तमान में पाकिस्तान ने इस प्रकार के विभिन्न वैचारिक और नागरिक समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने पाकिस्तान सरकार के अत्याचार के विरुद्ध अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था।

वर्तमान PoJK में "आज़ाद जम्मू और कश्मीर" (AJK, पाकिस्तान ने यह नाम दे रखा है) और गिलगित बाल्टिस्तान (G-B) का भू-भाग आता हैं, इसे पाक सेना ने 1947 में सशस्त्र कार्रवाई के जरिए बलपूर्वक अनैतिक रूप से अधिकृत कर लिया था। उस समय से इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश 'आजाद जम्मू और कश्मीर' का पकिस्तान ने दर्जा दे रखा है, जिसका स्वयं का राष्ट्रपति/ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के द्वारा नामित होता है| किन्तु वास्तविकता में यह न देश है और न ही प्रान्त। इसके राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार की वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है, शासन की समस्त शक्ति पाकिस्तान सरकार के पास है। इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति ने शासन के अन्याय के विरुद्द अपने विचार अभिव्यक्त किए, उनके ऊपर व्यापक रूप से हिंसा का प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र में व्यापक रूप से नागरिक अधिकारों हेतु सक्रिय कार्यकर्त्ता, क्षेत्रीय राजनैतिक दल के सदस्य और पत्रकारों की हत्या, अपहरण, शासकीय कारागार में मृत्यु और लापता हो जाना या कर देने की प्रक्रिया घटित हो रही है।

पीओजेके और जीबी दोनों में, स्थानीय शिकायतें प्रायः छुपा ली जाती हैं, और जनता की आवाज को शांत रखने हेतु मीडिया सेंसरशिप लगाई जाती है। यहाँ विभिन्न आंदोलन लगातार हो रहे हैं जैसे ख़राब जीवन स्थितियों के विरुद्ध आंदोलन, बुनियादी मानवाधिकारों का न होना इसके विरुद्ध आंदोलन, संपत्ति का अधिकार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन आदि। किन्तु पाकिस्तानी मिडिया के ब्लैकआउट नीति के कारण इस क्षेत्र के समाचार को व्यापक रूप से नहीं दिखाया जाता है। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रीय राजनेता और पत्रकार को बिना किसी आरोप के हिरासत में ले लिया गया, और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान में जनसांख्यिकी बदलाव कर दी है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के हेतु इस क्षेत्र की भूमि के शोषण के विरुद्ध भी यहाँ व्यापक आंदोलन हो

रहा है क्योकि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भी पाकिस्तान को लाभ पहुँचाना है, न कि इस क्षेत्र को । पाकिस्तान सरकार यहाँ की जमीनी हकीकत को समझते हुए अपने लाभ के अनुसार स्पष्ट रूप से कार्य कर रही है| इस दौरान मानवाधिकारों के हनन को ध्यान में रखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय जाँच एजेंसी और एनजीओ कार्य कर रहें है, उनका रास्ता अत्यंत कठिन है। हांगकांग स्थित 'एशियाई मानवाधिकार आयोग' **('Asian Human Rights Commission')** ने एक रिपोर्ट (अगस्त 2016) पेश किया है जिसमें पाकिस्तान पर इस क्षेत्र में आत्यंतिक क्रूरता और यातना के प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इसमें उल्लेख किया गया कि इस क्षेत्र में नियमित रूप से भारी पुलिस बल के प्रयोग से यहाँ के जनता में व्यापक रोष व्याप्त है।

विभिन्न गिलगित-बाल्टिस्तान आधारित संगठन और गिलगित-बाल्टिस्तान श्रमिक संगठन (**Gilgit-Baltistan Trade Union, GBTU**) ने **GBO 2018** को लेकर **5 अक्टूबर, 2018** को विरोध प्रदर्शन किया और इसे G-B के निवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन माना। अवामी एक्शन कमेटी **(AAC)** और गिलगित-बाल्टिस्तान ट्रेड यूनियन **(GBTU)** ने स्कार्दू, गिलगित, चिलास और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इस शिया बहुल क्षेत्र को धार्मिक निरंकुशता का प्रदर्शन करते हुए सुन्नी बहुल समुदाय के साथ मिलाया जा रहा है। यहाँ पर रत्तीभर भी स्वायत्तता और प्रजातंत्र नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि पाकिस्तान के 'नेशनल असेंबली' में इस क्षेत्र के व्यक्ति का किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं है, न ही चयन के रूप में और न ही नामित रूप में । ये कभी भी नेशनल असेंबली के भाग नहीं होते है।

पाकिस्तान अनाधिकृत जम्मू-कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय तरंग संगोष्ठी उन तमाम घटनाक्रमों की जाँच करने का प्रयास है जो इस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक असुरक्षा को बढ़ता है।